

भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या: 1889

गुरुवार, 28 जुलाई, 2022/ 06 श्रावण, 1944 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमानन क्षेत्र का विकास

1889. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

श्री सुधीर गुप्ता:

श्री सुब्रत पाठक:

श्री प्रतापराव जाधव:

श्री रवि किशन:

श्री रविन्दर कुशवाहा:

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:

श्री विद्युत बरन महतो:

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ता विमानन बाजार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा विमानन बाजार को बढ़ावा देने के लिए कौन सी विशेष योजनाएं तैयार की गई हैं;

(ख) क्या भारत वर्ष 2024 तक विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बन जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक तैयार की गई/कार्यान्वित की गई रूपरेखा और भविष्य के लिए बनाई गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का अंतरराज्यीय हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए सभी छोटे चालू न किए गए विमानपत्तनों को आरंभ करने का विचार है;

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितने विमानपत्तन चिन्हित किए गए हैं और अब कितने विमानपत्तनों पर कार्य प्रगति पर है; और

(च) उक्त कार्यों के कब तक पूरा होने की संभावना है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (च): जी हाँ। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजारों में से एक है। भारत पहले से ही तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है। वर्ष 2030 तक समग्र रूप से यह तीसरा सबसे बड़ा बाजार हो सकता है।

सरकार ने वर्ष 2016 में, राष्ट्रीय नागर विमानन नीति (एनसीएपी 2016) जारी की, जिसमें इस क्षेत्र के लिए विजन, मिशन और प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किए गए। इसने विमानन मूल्य श्रृंखला के 20 से अधिक पहलुओं को शामिल करते हुए प्रमुख कार्रवाई कदमों का भी प्रस्ताव दिया, जिनमें शामिल हैं: क्षेत्रीय संपर्क, सुरक्षा, संरक्षा, एयरलाइंस, हवाई अड्डे, द्विपक्षीय यातायात अधिकार, कोड-शेयर करार, हवाई नेविगेशन, हेलीकॉप्टर, कार्गो, निर्माण, अनुरक्षण और कौशल विकास आदि।

विमानन क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) और निजी हवाईअड्डा कंपनियों ने अगले पांच वर्षों में 90,000 रुपये से अधिक के अनुमानित पूंजीगत व्यय के साथ नए और मौजूदा हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा।

सरकार ने देश भर में 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना के लिए 'सैद्धांतिक' मंजूरी दे दी है। अब तक आठ ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे नामतः महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग और शिरडी, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, सिक्किम में पकयोंग, केरल में कन्नूर, आंध्र प्रदेश में ओर्वाकल, कर्नाटक में कलबुर्गी और उत्तर प्रदेश में कुशीनगर प्रचालनीकृत किए जा चुके हैं।

सरकार ने 2024 तक राज्य सरकारों, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, सिविल एन्क्लेव, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई), हेलीपैड और जल हवाई अड्डों के 100 अप्रचालित और अल्पप्रचालित हवाईअड्डों के पुनरुद्धार और विकास के लिए 4500 करोड़ रुपये की कुल लागत से 'अप्रचालित और अल्पप्रचालित हवाईअड्डों का पुनरुद्धार योजना' अनुमोदित की है। इस योजना के तहत 30 जून 2022 तक 2610 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं।

सरकार ने अक्टूबर 2016 में क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस)-उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) शुरू की थी ताकि हवाई यात्रा को आम जनता के लिए वहनीय बनाकर देश में अप्रचालित और अल्पप्रचालित हवाईअड्डों से क्षेत्रीय हवाई संपर्क में बढ़ौतरी की जा सके। 15 जुलाई 2022 तक, देश भर में 425 'उड़ान' मार्ग चालू किए जा चुके हैं, जिसमें 2 वाटर एयरोड्रोम और 8 हेलीपोर्ट सहित 68 'उड़ान' हवाईअड्डों को जोड़ा जा चुका है।